

प्रेषक,

विनोद फोनिया  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर, 2010

विषय: अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2095/नि०-5/एक(16)/भ०नि०रा०सै०(अ०आ०/2010-11 दिनांक 25 अगस्त, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत निम्नांकित पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित ₹ 31.96 लाख (₹ इकतीस लाख छियानब्बे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न विवरणानुसार धनराशि आपके निर्वर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदाष्टि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	पशु सेवा केन्द्र	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित/जारी स्वीकृति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	पशु सेवा केन्द्र, पैठाणी, अल्मोड़ा	12.24	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	पशु सेवा केन्द्र, फल्याटी, बागेश्वर	11.19	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
3	पशु सेवा केन्द्र, हबीबपुर, हरिद्वार	8.53	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
योग		31.96	.

(₹ इकतीस लाख छियानब्बे हजार मात्र)

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण पूर्व में स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग के पश्चात ही वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाए।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
  7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।
  8. जी०पी०डब्लू० फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
  9. स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े। निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाये।
  10. योजनान्तर्गत अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अब तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण, भौतिक/प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जाये।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-00-101-पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-0203-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-234(P)/XXVII-04/10 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)  
सचिव

संख्या: 2307 (1) / XV-1/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं हरिद्वार।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं हरिद्वार।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी० को बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(23/10)  
(एस०के० पन्त)  
अनु सचिव